भारत सरकार

उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्याः 2875

उत्तर देने की तारीख 5 अगस्त, 2026 (बुधवार)

14 श्रावण, 1948 (शक)

प्रश्न

पीएम-डिवाइन के अंतर्गत उपलब्धियां

2875. **श्री दिलीप शइकीयाः**

क्या **उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) 6,600 करोड़ रुपये के परिव्यय वाली पूर्णतः केंद्र पोषित योजना 'प्रधानमंत्री की उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास पहल' (पीएम-डिवाइन) के अंतर्गत हासिल की गई उपलब्धियां क्या हैं, विशेषकर विशिष्ट कैंसर देखभाल, स्मार्ट जलापूर्ति, शैक्षणिक आधुनिकीकरण और पहाड़ी रोप-वे कनेक्टिविटी जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण अवसंरचना, आजीविका के अवसरों और समाज कल्याण के संबंध में क्या विशिष्ट उपाय किए गए हैं;

(ख) क्या उत्तर पूर्वी क्षेत्र में सुगम और सुदृढ़ लॉजिस्टिक्स कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए पीएम-डिवाइन परियोजनाओं के रणनीतिक कार्यान्वयन को 'पीएम गति शक्ति' ढांचे के साथ एकीकृत किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उत्तर पूर्व विशेष अवंसरचना विकास योजना (एनईएसआईडीएस), उत्तर पूर्वी परिषद (एनईसी) और संबद्ध योजनाओं के तहत स्वीकृत लगभग 3,700 परिसंपत्तियों के निर्माण में तेजी लाने के लिए, जिनमें से 27,900 करोड़ रुपये से अधिक की अनुमोदित लागत पर 2,700 से अधिक परिसंपत्तियों का कार्य पूरा किया जा चुका है, किए गए प्रशासनिक उपायों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास राज्य मंत्री

(डॉ. सुकान्त मजूमदार)

(क) अक्तूबर, 2022 में स्कीम के प्रारंभ से लेकर दिनांक 31.07.2026 तक, प्रधान मंत्री पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास पहल (पीएम-डिवाइन) स्कीम के अंतर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, पर्यटन, आजीविका आदि सहित विभिन्न क्षेत्रों के लिए ₹6,501.79 करोड़ की कुल लागत वाली 53 परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई है।

(ख) और (ग) पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान (एनएमपी) के उद्देश्यों के अनुरूप अवसंरचना परियोजनाओं की योजनाओं, समन्वय एवं निगरानी को सुदृढ़ बनाने के लिए उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय की सभी परियोजनाओं, जिनमें पीएम-डिवाइन की परियोजनाएँ भी शामिल हैं, को उनके अक्षांश एवं देशांतर निर्देशांकों के साथ सटीक स्थल मैपिंग करते हुए पीएम गति शक्ति पोर्टल के साथ एकीकृत किया गया है। इससे इन परियोजनाओं को एक सार्वजनिक भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) प्लेटफॉर्म पर देखा जा सकता है, जिससे उनकी प्रगति की निगरानी सुनिश्चित होती है तथा संबंधित हितधारकों के बीच बेहतर समन्वय को बढ़ावा मिलता है।

मंत्रालय द्वारा अपनी परियोजनाओं, जिनमें 'पूर्वोत्तर विशेष अवसंरचना विकास स्कीम (नेसिड्स)' तथा 'पूर्वोत्तर परिषद् की स्कीम (सोनेक)' की परियोजनाएँ भी शामिल हैं, के कार्यान्वयन की निगरानी राज्य सरकारों एवं कार्यान्वयन एजेंसियों के साथ समय-समय पर समीक्षा बैठकें आयोजित करके की जाती हैं, जिसमें जियो-टैग एवं टाइम-स्टैम्प्ड फोटोग्राफों पर आधारित डैशबोर्ड, मंत्रालय/उत्तर पूर्वी परिषद्/क्षेत्रीय तकनीकी सहायता इकाइयों (एफटीएसयू)/परियोजना गुणवत्ता पर्यवेक्षकों (पीक्यूएम)/ तृतीय पक्ष तकनीकी निरीक्षण एजेंसियों (टीपीटीआई) द्वारा क्षेत्रीय निरीक्षण एवं स्थल दौरा आदि के माध्यम से परियोजनाओं की निगरानी की जाती है।

इन समीक्षा बैठकों के माध्यम से परियोजनाओं के कार्यान्वयन में उत्पन्न होने वाली बाधाओं, यदि कोई हों, की पहचान की जाती है तथा संबंधित राज्य सरकारों/कार्यन्वयन एजेंसियों को परियोजनाओं की निगरानी व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने, कार्यान्वयन में तेजी लाने, निधि का समयबद्ध उपयोग सुनिश्चित करने तथा निर्धारित कार्यान्वयन कार्यक्रम का अनुपालन करने के लिए आवश्यक परामर्श दिया जाता है।

*****